

# Workshop on upcoming technologies for effluent treatment in sugar units

PIONEER NEWS SERVICE ■ KANPUR

To control the effluent generation and pollution released from sugar industries and distilleries in Ganga Basin the Central Pollution Control Board had sought the help of National Sugar Institute, Kanpur to suggest ways and means for controlling effluent generation from sugar factories. The institute experts had already toured 100 sugar factories and distilleries to assess the extent of effluent generation and adequacy of their effluent treatment plants. This was stated by Director of NSI, Prof Narendra Mohan while addressing the one-day workshop on 'Upcoming Technologies for effluent treatment in sugar industries' on Tuesday. He called upon the sugar factories to ensure compliance of the guidelines issued by the CPCB in January 2016. He said as a result the total effluent generation had been limited to 200 litres per tonne of sugarcane crushed.

He expressed concern over the existing status of water management and effluent treatment system which was found wanting in most of the factories the team visited in India. He said the sugar factories must ensure proper flow meters for fresh water usage and effluent inlet to effluent treatment plant. He said sugar factories should install the real time monitoring system having connectivity with CPCB and UPSPCB server to assess the quantity and quality of effluent on continuing basis. He also emphasised upon implementing hot and cold water models developed by the institute fanless cooling towers and condensate polishing units for minimising fresh water usage



NSI Director Prof Narendra Mohan addressing a workshop on effluent treatment in sugar mills on Tuesday. *Pioneer*

and the effluent discharge. He said the special team set up will be visiting the sugar units for the crushing season 2017-18.

Dr Santosh Kumar explained the details of various effluent treatment systems which can be put in use to get the desired quality of discharge particularly in achieving a BoD value of less than 30mg/litre. He said as observed the sugar factories were still discharging substantial quantities of effluent without treatment which was not desirable. He said sugar factories were not equipped for treatment of wastewater from spray pond which contained sulphur and hence the existing ETPs needed to be upgraded. He said precipitation and removal of sulphates and sulphites using milk of lime and microsettlers or decanters can solve the problem. Addressing the special session DK Saxena said adsorption had received great attention in the recent years as an efficient process for wastewater treatment. He said besides COD several other substances like dyes, phenolic compounds and heavy metals can be effectively removed from the wastewater by adsorption. He said although activat-

ed carbon had found wide acceptance by virtue of its high removal capacity and adaptability for a wide range of wastewater substances. He said low cost adsorbents like fly ash, wood, peat, waste rubber, lignite, sawdust, rice husk etc. had received considerable interest because of their low cost and easy availability. He said work had been carried out to assess the suitability of bagasse fly ash which was a waste from sugar industry, for removal of COD and colour from synthetic wastewater prepared from gur solution and sugar mill effluent.

He said sugar was one of major product in India and water management in the industry was one of major problem. He said due to this there was lots of effluent generated to effluent treatment plant and thus efficiency getting reduced for the treatment to be achieved. He said industry can be well maintained if proper water management activities can be practiced and applied in the required area. He said recycling of condensate, segregation of high strength and low strength effluent, proper operation of ETP led to a well maintained water manage-

ments in the industry and led to reduction of cost on water. He said a well operated and maintained ETP will not have any problem and can achieve the prescribed norms by statutory board.

Dr Seema Paroha addressing the seminar said sugar production in India had been cyclic in nature and an estimated 75 per cent of the population depended on the sector either directly or indirectly. She said sugar industry was also expected to develop further, thereby offering more employment opportunities to a number of semi-skilled and skilled workers in the rural areas of the country thereby contributing towards their development. She said the sugar industry also supported diversified ancillary activities and skills that supported the local economy. She said the dependent population created substantial demand for local goods and services. She said the sector also had major social and economic impact on the nation as it was a green industry and was largely self-sufficient in energy needs through utilisation of bagasse for generating electricity and steam. She said the sugar industry generated surplus exportable energy through cogeneration and contributes to reducing the energy deficit that India was currently facing. She said sugarcane was grown in semi-tropical region and accounted for around two-third of world sugar production.



## गंगा बेसिन क्षेत्र में प्रदूषण कम करने को शर्करा संस्थान से मांगी मदद

कानपुर। गंगा बेसिन क्षेत्र में स्थित चीनी मिलों व आसवनियों के उत्प्रवाह की मात्रा कम करने व इससे होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कानपुर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) से मदद मांगी है। इस क्रम में एनएसआई निदेशक प्रो.नरेन्द्र मोहन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जो व्यापक अध्ययन कर अपना सुझाव देगी। संस्थान के विशेषज्ञों ने चीनी मिलों व आसवनियों में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की पर्याप्तता के जानकारी के लिए करीब 100 मिलों का निरीक्षण भी कर लिया है।

उक्त कवायद के क्रम में ही मंगलवार को एनएसआई में 'अपकमिंग टेक्नालॉजिज फार इफ्लूयेंट ट्रीटमेंट इन शुगर इंडस्ट्रीज' विषय पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गयी। कार्यशाला में एचपीसीएल बायोप्यूल्स के सीईओ डीके सक्सेना बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। उप्र, उत्तरांचल व बिहार की चीनी मिलों के प्रतिनिधियों ने भी भागीदारी की। एनएसआई निदेशक प्रो.नरेन्द्र मोहन ने चीनी मिल प्रतिनिधियों से कहा कि वे जनवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित



राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में कार्यशाला को संबोधित करते निदेशक प्रो.नरेन्द्र मोहन।

करें। बोर्ड ने चीनी मिलों से उत्प्रवाहित जल की मात्रा को 200 लीटर प्रति टन गन्ना तक

### राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में विशेषज्ञ समिति बनी

सीमित करने को कहा है। उत्प्रवाह की गुणवत्ता एवं मात्रा के संही ऑक्लेंट के लिए जरूरी संयंत्रों को लगाने पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने बताया कि पेराई सत्र 2017-18

में संस्थान के विशेषज्ञ चीनी मिलों में प्रदूषण नियंत्रण का पुनः आकलन करेंगे। संस्थान के सहायक आचार्य डॉ.संतोष कुमार व आचार्य जैव रसायन डॉ.सीमा परोहा ने भी प्रदूषण नियंत्रण के विभिन्न उपायों की चर्चा की। संस्थान के मुख्य अभिकल्प अभियंता जेपी श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों का निर्माण करने वाली विभिन्न कंपनियों ने इस अवसर पर अपनी तकनीकों के बारे में प्रस्तुतिकरण भी दिये।

## प्रदेश की चीनी मिलें भी कर रही गंगा को प्रदूषित

कानपुर | कार्यालय संवाददाता

गंगा बेसिन में स्थित चीनी मिलें गंगा जल को प्रदूषित कर रही हैं। मिलों से निकला पानी नालों के जरिए गंगा में पहुंच रहा है। प्रदूषित जल के ट्रीटमेंट की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। बढ़ रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) से मदद मांगी है। संस्थान के निदेशक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। यह टीम चीनी मिलों का दौरा कर प्रदूषण कम करने के उपायों पर सुझाव देगी।

समिति ने अब तक 100 से अधिक चीनी मिलों को भ्रमण भी कर लिया है। इसी क्रम में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मंगलवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड की चीनी मिलों के



विचार रखते प्रो. नरेन्द्र मोहन।

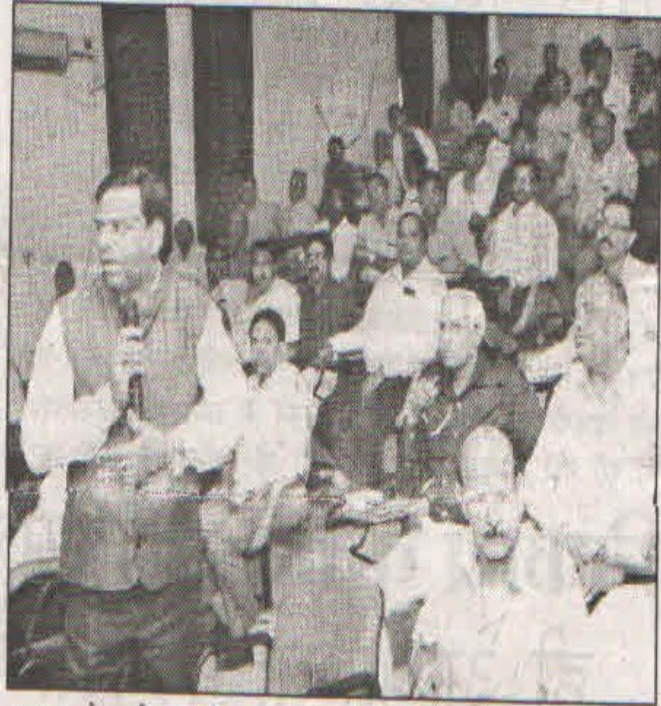
प्रतिनिधियों को संस्थान के निदेशक प्रो. नरेन्द्र मोहन ने प्रदूषण नियंत्रण का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जनवरी 2016 के दिशा-निर्देश के पालन को सुनिश्चित किया जाए। मिलों में ताजे पानी की खपत की मात्रा घटाने पर बल दिया। संस्थान के डॉ. संतोष कुमार ने चीनी मिलों के उत्सर्जित जल के परिशोधन की तकनीकी के बारे में बताया। कार्यशाला में कई कंपनियों ने तकनीकी की प्रस्तुति भी दी।



# चीनी मिलों से निकलने वाले उत्प्रवाह की मात्रा कम करने के लिए समिति गठित

चेतना समाचार सेवा

कानपुर, 24 अक्टूबर। गंगा बेसिन में स्थित चीनी मिलों एवं आसवनियों से निकलने वाले उत्प्रवाह की मात्रा कम करने तथा इस प्रवाह से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय शर्करा संस्थान से मदद करने को कहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जो कि चीनी मिलों के उत्प्रवाह से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उपाय बारे में सुझाव देगी। प्रदूषण नियंत्रण हेतु चीनी मिलों में



उत्प्रवाह के शोधन की नवीनतम दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जानकारी देने हेतु संस्थान में एक किया गया।